भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 2580**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 16 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात प्रदर्शन

2580. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वित्त वर्ष 2026 की पहली और दूसरी तिमाहियों में दर्ज किए गए अब तक के सर्वोच्च तिमाही निर्यात कार्य-निष्पादन के प्रमुख कारकों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या विशिष्ट क्षेत्रों ने इस अवधि के दौरान निर्यात वृद्धि को बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार को वित्त वर्ष 26 की शेष तिमाहियों के लिए सुदृढ़ निर्यात कार्य-निष्पादन जारी रहने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या मौजूदा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत की निर्यात गति को बनाए रखने के लिए उपाय किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) क्या भारतीय निर्यातकों की, विशेषकर उच्च विकास वाले वैश्विक बाजारों में दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए कदम उठाने की योजना बनाई जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही (एच1) में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। अप्रैल-सितंबर 2025 के दौरान पण्यवस्तु और सेवाओं दोनों को मिलाकर कुल निर्यात 418.6 बिलियन अमेरीकी डॉलर तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5.8% की वृद्धि है और यह पहली छमाही निर्यात के लिए एक नया सर्वकालिक उच्च स्तर है। विशेष बात यह है कि लगातार वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2025) और दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2025) दोनों ने अपनी–अपनी तिमाहियों के लिए अब तक का सबसे अधिक निर्यात स्तर दर्ज किया।

भारत का कुल संचयी निर्यात प्रदर्शन मजबूत बना हुआ है। अप्रैल-अक्टूबर 2025 के लिए कुल निर्यात वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 4.1% बढ़कर 488.1 बिलियन अमेरीकी डॉलर हो गया। पण्यवस्तु निर्यात में 0.5% की वृद्धि हुई,

जो 253.9 बिलियन अमेरीकी डॉलर तक पहुँच गया, जबकि इसी अवधि के दौरान सेवाओं का निर्यात 8.2% बढ़कर 234.2 बिलियन अमेरीकी डॉलर हो गया।

इसके अलावा, वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद कई बड़े क्षेत्र मज़बूत वृद्धि का प्रदर्शन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली रही, जिसमें 37.8% की तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। कृषि संबंधित श्रम गहन श्रेणियों में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई – काजू (28.3%), अन्य अनाज (25.5%), मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद (24.0%), चाय (15.2%), कॉफी (12.3%), फल और सब्जियां (6.2%), चावल (5.5%), और अनाज से बने उत्पाद (3.9%)। समुद्री उत्पादों का निर्यात 16.2% बढ़ा, अभ्रक और अन्य अयस्कों सहित खनिज निर्यात में 11.9% की वृद्धि हुई, जबकि दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स में 4.7% की बढ़ोतरी हुई। इंजीनियरिंग वस्तुओं, जो भारत का सबसे बड़ा निर्यात सेगमेंट है, में 1.7% की स्थिर वृद्धि दर्ज की गई। इसी अवधि में, पेट्रोलियम, वस्त्र, प्लास्टिक आदि कुछ प्रमुख श्रेणियों में बाहरी बाज़ार स्थितियों के कारण गिरावट देखी गई।

(ग) और (घ): लगातार बनी हुई वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का निर्यात प्रदर्शन मज़बूत बना हुआ है। सरकार आरबीआई के व्यापार राहत उपायों, निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के ज़रिए घरेलू मांग को बढ़ाने, नए निर्यात संवर्धन मिशन जैसे निर्यात संवर्धन के उपायों, जो हमारे निर्यातकों को सहयोग और सहायता प्रदान करते हैं, नए देशों के साथ एफटीए करने और मौजूदा एफटीए का बेहतर उपयोग करने जैसी व्यापक बहु-आगामी कार्यनीति के ज़रिए कार्य करती है। यह प्रत्यासा है कि ये उपाय भारत के व्यापार संबंधों में विविधीकरण और लचीलेपन को भी बढ़ाएंगे।

(ड.): वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत के संवर्धित एकीकरण को देखते हुए, सरकार ने निर्यातकों को बढ़ावा देने और घरेलू विनिर्माण को मज़बूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ उपायों में निर्यातकों प्रोत्साहन प्रदान करना, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए ट्रेड प्रक्रियाओं को आसान बनाना, और भारतीय उत्पादों के लिए बाजार पहुँच बढ़ाने के लिए अलग-अलग देशों और ग्रुप्स के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर बातचीत करना शामिल है। विदेशों में वाणिज्यिक मिशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों, कमोडिटी बोर्डो/प्राधिकरणों और उद्योगिक संगठनों के साथ निर्यात कार्य निष्पादन की नियमित निगरानी की जा रही है और समय-समय पर सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा, नई विदेश व्यापार नीति 2023 भारत को वैश्विक बाजार के साथ एकीकृत करने और इसे एक भरोसेमंद और विश्वसनीय व्यापार साझेदार बनाने का एक ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करती है। इससे भारत के व्यापार प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धात्मकता में और सुधार होने की प्रत्यासा है।

वाणिज्य विभाग नियमित रूप से सम्बंधित मंत्रालयों/विभागों और अन्य हितधारकों की समय-समय पर और विभिन्न स्तरों पर आयात के मुद्दे पर निगरानी कर रहा है और उन्हें जागरूक कर रहा है, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित व्यापक कार्यनीति के आधार पर आयात पर निर्भरता कम करना है: (i) घरेलू आपूर्ति सम्बंधी बाधाओं को दूर करना और घरेलू उत्पादन के अवसरों पर ध्यान देना/क्षमता बढ़ाना; (ii) व्यापार उपचार के

विकल्पों का समय पर उपयोग करना; (iii) गुणवत्ता नियंत्रण; (iv) उत्पत्ति संबंधी नियमों को लागू करना; (v) टैरिफ उपाय/इनवरटिड शुल्क में सुधार; और (vi) आयातित वस्तुओं की निगरानी करना।

सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए निर्यात प्रोत्साहन मिशन (ईपीएम) योजना को मंजूरी प्रदान की है, जिसका उद्देश्य- विशेष रूप से एमएसएमई के लिए भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना है। ईपीएम को दो एकीकृत उप-योजनाओं के माध्यम से परिचालित किया जाएगा:

- निर्यात प्रोत्साहन, जो ब्याज अनुदान, निर्यात फैक्टरिंग, निर्यात ऋण के लिए कोलैटरल गारंटी, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए ऋण, और ऋण संवर्धन सहयोग जैसे तरीकों से व्यापार वित्त तक पहुंच बेहतर पहुँच बनाने पर केंद्रित है; और

- निर्यात दिशा, जो निर्यात गुणवत्ता और अनुपालन संबंधी सहयोग, अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग तथा पैकेजिंग, बाजार पहुँच पहल, निर्यात् लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग, एवं व्यापार आसूचना जैसे अन्य व्यापार सक्षमकर्त्ताओं पर केंद्रित है।

ईपीएम एक सहयोगी फ्रेमवर्क पर आधारित है जिसमें वाणिज्य विभाग, एमएसएमई मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, और वित्तीय संस्थानों, निर्यात संवर्धन परिषदों, कमोडिटी बोर्डों, उद्योग संघों और राज्य सरकारों सहित अन्य प्रमुख हितधारक शामिल हैं।

निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना को भी मंजूरी दी गई है ताकि राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) को 100% ऋण गारंटी कवरेज प्रदान किया जा सके, ताकि एमएसएमई सहित पात्र निर्यातकों को 20,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त संपार्श्विक-मुक्त ऋण सुविधाएँ प्रदान की जा सकें। इस योजना से भारतीय निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने और नए व उभरते बाजारों में विविधीकरण को बढ़ावा मिलने की प्रत्याक्षा है। संपार्श्विक-मुक्त ऋण पहुँच से लिक्विडी मजबूत होगी, सुचारू व्यावसायिक परिचालन सुनिश्चित होगा और 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत की प्रगति को मजबूती मिलेगी।

व्यापार राहत उपाय:-भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पात्र प्रभावित निर्यातकों के लिए व्यापार राहत उपाय भी शुरू किए हैं, जिसमें ऋण चुकौती स्थगन और निर्यात ऋण की अवधि बढ़ाने का प्रावधान शामिल है।

मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठाना:- सरकार का लक्ष्य निर्यात विविधीकरण को बढ़ावा देना है और इसने अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ 15 मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और 6 अधिमान्य व्यापार समझौतों (पीटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार सभी हितधारकों के साथ मिलकर कार्य कर रही है ताकि हमारे निर्यातक जापान, कोरिया, यूएई आदि जैसे प्रमुख बाजारों के साथ भारत के एफटीए

के लाभों का बेहतर उपयोग कर सकें और हाल ही में ईएफटीए देशों और यूके के साथ संपन्न एफटीए से उत्पन्न अवसरों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें। सरकार यूरोपीय संघ, पेरू, चिली, न्यूज़ीलैंड, ओमान आदि के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी एफटीए को शीघ्र संपन्न करने के लिए भी वार्ता कर रही है।

सरकार अमेरिकी टैरिफ उपायों के उभरते प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए निर्यातकों, निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी), उद्योग संघों और राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के साथ नियोजित है।

विविधीकरण उपाय:- निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप, यूरोपीय संघ और रूस को निर्यात के लिए सूचीबद्ध मत्स्य पालन प्रतिष्ठानों की संख्या में हाल ही में वृद्धि हुई है। मत्स्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से देश में मत्स्य पालन और जलीय कृषि के विकास के लिए कुल 21274.13 करोड़ रुपये के साथ परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। इससे इस क्षेत्र में भारत के निर्यात में दोगुने से अधिक की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2013-14 में 30,213 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 62,408 करोड़ रुपये हो गया है, जिसमें मूल्यवर्धित उत्पादों का हिस्सा 2% से बढ़कर 11% हो गया है।

****